एस.टी.रमेश

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

20 फ़रवरी 2007

[डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन और अल्तमस कबीर, जे.जे.]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 868/2007

कनार्टक उच्च न्यायालय, बेंच बेंगलुरू के रिट याचिका संख्या 33105(एस-कैट) में पीरिरत अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.9.2005 से उत्पन्न।

अरविंद वी. सावंत, श्री नारायण, नवकेश बत्रा और संदीप नारायण (बी.एस.नारिन एंड कंपनी के लिए), अपीलकर्ताओं की ओर से

सुनील मैथ्यू, संजय आर. हेज और संथानम स्वामीनाथन, उत्तरदाताओं की ओर से।

प्रत्यर्थी संख्या-2 व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन, जे. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील, अपीलकर्ता एस.टी. रमेश, आई.पी.एस., जो अब पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, द्वारा दायर 2000 की रिट याचिका संख्या 33105 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.9.2005 के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें रिट याचिका को खारिज कर दिया और दूसरे उत्तरवादी को खरचा दिलाया

गया।

3. अपीलकर्ता ने मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार के दिनांक 9.12.1997 के पत्र में शामिल विभिन्न शीर्षकों के तहत प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना को रद्द करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, बैंगलोर के समक्ष मूल आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने, अपने आदेश से, दूसरे उत्तरवादी, श्री सी. दिनाकर, आईपीएस को 3000/- रुपये का खरचा दिलाने के साथ मूल आवेदन को खारिज कर दिया।

4. इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। अपीलकर्ता ने इस अपील में ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया।

5. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम मुख्य सचिव के दिनांक 9.12.1997 के पत्र में शामिल विभिन्न शीर्षकों के तहत प्रतिकूल टिप्पणियों की संसूचना को पुनः उद्धृत करेंगे जो इस प्रकार है:

प्रमुख शासन सचिव

विधान सौधा

बेंगलुरु - 560001

डी. ओ. नं. सी एस 26 आई पी एस सी आर 9

प्रिय श्री रमेश 16.10.1996 से 15.3.1997 की अवधि के लिए आपकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में आपके समग्र प्रदर्शन को 'औसत' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और निम्नलिखित प्रतिकूल टिप्पणियाँ भी दर्ज

की गई हैं:

आउटपुट की गुणवत्ता:

उन्होंने अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं किया और ऐसा आभास दिया मानो सीओडी में उनका कार्यकाल एक प्रवास था। शायद, यह सी ओ डी के लिए एक बाधा बन गई। इसमें और अधिक जिम्मेदारी जोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी और यह अभी तक और आगे नहीं का रवैया था।

ज्ञान और कार्य क्षेत्र: वह पेशे और इसके संबंधित अनुप्रयोग के जानकार हैं, लेकिन, फिर भी, उनके 'प्रतिमान' ने उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से रोक दिया।

नेतृत्व की विशेषता:

वह सीओडी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिभाषित पर्यावरण और कार्य संस्कृति का मूल्यांकन नहीं कर सका और यह नए विचारों या काम के नए तरीकों के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। उनके अंदर का 'मार्गदर्शक' शीतनिद्रा में चला गया।

प्रबंधन गुण:

इस कॉलम को ठीक पिछले कॉलम के साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रबंधन के सभी गुण, जो उनमें मौजूद थे, चित्रदुर्ग में एक युवा छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में घटनास्थल पर नहीं जाने के कारण खतरनाक हद तक निष्क्रिय हो गए।

पहल और योजना क्षमताए:

एकमात्र अवसर पर, जब आंदोलनकारियों का एक समूह, हैंडबिल

के माध्यम से उचित सूचना के बाद, सीओडी परिसर के बाहर आया और बैठ गया, तो वह, खुद को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, उसी समय कार्यालय से बाहर चला गया और इस प्रक्रिया में, उसके वरिष्ठ को स्थिति को शांत करना पड़ा।

निर्णय लेने की क्षमता: 824 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2007] 2 एस.सी.आर.

उनकी निर्णय लेने की क्षमता उनके 'प्रतिमान' द्वारा संचालित होती थी।

संसूचना कौशल:

उनकी अंग्रेजी पर पकड़ है और उनकी कुछ फाइलों में, जिनमें उन्हें विस्तृत होना पसंद था, उन्होंने खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। हालाँकि, कन्नड़ में उनकी अभिव्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है। उनके तर्कों की प्रस्तुति भी अच्छी है लेकिन एक निश्चित अवसर पर; उन्होंने डीजीपी के साथ एक अप्रिय स्थिति पैदा कर दी जिसे पूरी तरह से टाला जा सकता था।

मूल्यांकन क्षमता:

अपने कुछ अधीनस्थों के प्रति उनका मूल्यांकन अन्यत्र उनके साथ हुए कुछ 'उनके पिछले अनुभवों' के कारण धूमिल हो गया था।

अंतर-वैयक्तिक संबंध और टीम वर्क:

अपने एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनके व्यावसायिक संबंधों में विद्वेषता थी। यह दूसरों के साथ गुनगुना था.

सामान्य असर व्यक्तित्व:

मुस्कुराने के अलावा कुछ भी।

सामाजिकता:

अलग रहना पसंद करता है.

कर्तव्य के प्रति समर्पण:

उसकी सुविधा पर निर्भर करता है.

ब्योरे पर ग़ौर:

हाँ लेकिन अपना समय लेता है प्रतिक्रिया समय तेज़ नहीं है.

सैद्धांतिक रुख अपनाने की क्षमता:

यह उसके 'प्रतिमान' से धूमिल हो गया है।

सामान्य आकलन

उसके पास बेहतर परिणाम देने की क्षमता है, लेकिन अगर वह अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार्यता नहीं बिठा पाता है तो वह पूरे संगठन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा।

एक अहंकारी अधिकारी। कार्य के प्रति उसका ज्ञान अच्छा है, परंतु वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष नहीं हो पाता। कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय एसडी/-

पढ़ने योग्य नहीं

(बी.के.भट्टाचार्य)"

6. अपीलकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन का विरोध करते हुए,

उत्तरदाताओं ने अपना लिखित जवाब दाखिल किया। अपीलकर्ता द्वारा दिए गए तर्कों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए, उत्तरदाताओं ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उन्होंने नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन से निपटने में उचित कार्रवाई की है। यह भी कहा गया है कि नियमों और टिप्पणियों के नियम 8 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार प्रतिकूल टिप्पणियां लिखने वाले व्यक्तियों की पहचान का खुलासा किए बिना उपयुक्त प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी दोनों द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध पर उपयुक्त प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी और चूंकि दोनों प्राधिकारियों ने उनके द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को उचित ठहराया है, इसलिए पहले उत्तरवादी को प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का कोई कारण नहीं मिलता है।.

7. अपीलार्थी का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

अपीलकर्ता को वर्ष 1976 में भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया था और केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य को आवंटित किया गया था। अप्रैल, 1997 के महीने में, अपीलकर्ता को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 1.4.1996 से 30.6.1996 तक, अपीलकर्ता ने पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर निदेशक (सुरक्षा और सतर्कता), केएसआरटीसी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। जुलाई माह में, अपीलकर्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा में आयोजित ओलंपिक खेलों में

प्रतिनियुक्त किया गया था। वह कुछ समय तक अनिवार्य प्रतीक्षा पर थे। 16.10.1996 को, अपीलकर्ता को पुलिस उप महानिरीक्षक, सीआईडी के रूप में तैनात किया गया था और उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक के कैडर में अपनी पदोन्नति पर 17.4.1997 को उक्त पद छोड़ दिया।

8. पत्र दिनांक 9.12.1997 द्वारा, मुख्य सचिव ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि 16.10.1996 से 15.3.1997 तक की अवधि के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में, समग्र प्रदर्शन को "औसत" के रूप में वर्गीकृत किया गया था और कुछ प्रतिकूल टिप्पणियाँ दर्ज की गई थीं। पत्र दिनांक 9.12.1997 की प्राप्ति पर, अपीलकर्ता ने अखिल भारतीय सेवा (गाेपनीय नामावली) नियम, १९७० (संक्षेप में "नियम) के नियम ९ द्वारा प्रदान किए गए अनुसार अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता को दिनांक 19.6.1999 का एक आदेश प्राप्त हुआ जिसके

द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए अपीलकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम,1985 (संक्षेप में, "अधिनियम") की धारा 19 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग के साथ O.A.No. 981/1999 प्रस्तुत की।

9. अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के समर्थन में मुख्य आधार यह है कि वे सभी टिप्पणियां उसके खिलाफ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के साथ-साथ दूसरे उत्तरवादी (सी.दिनाकर) की ओर से अक्षमता, निष्पक्षता की

कमी और हताशा का परिणाम हैं, जो प्रासंगिक समय पर पुलिस महानिदेशक, सीओडी के रूप में कार्यरत थे। उपरोक्त आधारों के अलावा, अपीलकर्ता ने कई अन्य आधारों पर भी आक्षेपित आदेश पर हमला किया, जिसमें कहा गया कि नियमों में वर्णित नियम 5 और 6 की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन किया गया है और दूसरे उत्तरवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों को नियमों में वर्णित नियम 6 के तहत वैधानिक शक्ति का दुराशय से उपयोग करते हुए और उक्त प्रतिकूल टिप्पणियाँ पूर्वोक्त प्रावधानों, जो अनिवार्य है, के उल्लंघन में की गई थीं, जिससे वे अवैध हैं, शून्य हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं और जो आदेश बिना मस्ष्तिक का प्रयोग किए दिया गया और दिनांक 19.6.1999 का आक्षेपित आदेश अन्यथा अनुचित, अन्यायपूर्ण और कानून और तथ्यों के विपरीत है।

10. मूल आवेदन का कर्नाटक राज्य और अन्य उत्तरदाताओं द्वारा विरोध किया गया था और ट्रिब्यूनल के समक्ष दूसरे उत्तरवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां प्रासंगिक अवधि के लिए लिखी गई थीं जब उन्होंने उप महानिरीक्षक (सीओडी) के रूप में काम किया था और अपीलकर्ता के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी श्री विजय सासनूर थे, जो तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, सीओडी थे और दूसरे उत्तरवादी, जो उस समय पुलिस महानिदेशक, सीओडी के रूप में कार्यरत थे, समीक्षा प्राधिकारी थे; अपीलकर्ता द्वारा दूसरे उत्तरवादी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रेरित, पूरी तरह से निराधार और

झूठे हैं।

11. ट्रिब्यूनल ने अभिव्यक्त किया कि अपीलकर्ता द्वारा दूसरे उत्तरवादी के विरूद्ध लगाए गए आरोप अपमानजनक एवं दुभार्वनापूर्ण हैं और इससे दूसरे उत्तरवादी को व्यक्तिगत रूप से गंभीर असुविधा और शर्मिंदगी हुई है और कनार्टक सरकार के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ समुचित कार्रवाई शुरू करना उचित है। दूसरे उत्तरवादी श्री सी. दिनाकर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अपना मामला प्रस्तुत किया।

12. हमने विवादित वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का अवलोकन किया है जो कि 4 महीने और 19 दिनों की संक्षिप्त अवधि के लिए है यानी 16.10.1996 से 15.3.1997 तक, जिस अवधि के लिए दूसरा उत्तरवादी समीक्षा प्राधिकारी था, पहली छमाही में, अन्य बातों के साथ-साथ अपीलकर्ता को अटलांटा, यू.एस.ए. में ओलंपिक खेलों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और इस संक्षिप्त अवधि में कोई समीक्षा नहीं हुई थी। दूसरे उत्तरवादी सी. दिनाकर, जो व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुए, ने तर्क दिया कि रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा लिखी गई विवादित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमों के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप हैं। रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणियों को दुर्भावना के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है या उनकी निंदा नहीं की जा सकती है। समीक्षा प्राधिकारी द्वारा किया गया एकमात्र परिवर्द्धन निम्नलिखित हैं,

अहंकारी अधिकारी, उसका ज्ञान और कार्य अच्छा है, लेकिन वह अपने

कर्तव्यों के निर्वहन में वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष नहीं हो सकता।"

13. दूसरे उत्तरवादी के अनुसार, नियम 5(3) में वर्ष के एक भाग के लिए टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग की परिकल्पना की गई है और इसलिए, रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा विवादित टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग में कमियां नहीं ढूंढीं जा सकती है। सुनवाई के समय, हमारा ध्यान अपीलकर्ता द्वारा मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार को दिनांक 18.1.1998 को भेजे गए पत्र की ओर आकर्षित करवाया गया, जो कि मुख्य सचिव के दिनांक 9.12.1997 के पत्र, जिसके द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की संसूचना दी गई थी, से जवाब में दिया था। हमने दिनांक 18.1.1998 का संपूर्ण जवाब पढ़ा है। हमारा ध्यान कर्नाटक सरकार की कार्यवाही (अनुसंलग्नक पी-3) की ओर भी आकर्षित किया गया था, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा पारित आदेश था, जिसमें उल्लिखित कारणों से टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर दिया गया था। उक्त आदेश पारित करने से पहले सरकार ने अधिकारियों, अर्थात् रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा करने वाले प्राधिकारी, जिन्होंने प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की हैं, की टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता के अनुरोध की भी जांच की है और पाया है कि प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का कोई आधार नहीं है।

14. हमारे अनुरोध पर, रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा दी गई टिप्पणियों को भी हमारे ध्यान में लाया गया और हमने उसका अध्ययन किया है। इन परिस्थितियों में, कर्नाटक सरकार ने प्रतिकूल टिप्पणियों को दर्ज करने वाले अधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त

करने के बाद पाया कि प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का कोई आधार नहीं है और तदनुसार प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया।

15. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सभी प्रतिकूल टिप्पणियाँ रिपोर्टिंग प्राधिकारी, स्वर्गीय श्री विजय सासनूर द्वारा दर्ज की गईं थीं। हालाँकि, द्वेष और दुर्भावना का आरोप लगाते हुए आक्षेपित प्रतिकूल टिप्पणियों के हमले का पूरा आधार अपीलकर्ता द्वारा केवल दूसरे उत्तरवादी के खिलाफ बनाया गया था। मूल आवेदन में लिए गए आधार और अपीलकर्ता के अभ्यावेदन में उल्लिखित आधार सभी अपीलकर्ता की गलत धारणा पर आधारित हैं कि दूसरा प्रतिवादी ही प्रतिकूल टिप्पणियों का लेखक है और दूसरा प्रतिवादी उसके प्रति पक्षपाती है और इसलिए उसने जानबूझकर प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में अपीलकर्ता के खिलाफ ये टिप्पणियाँ लिखीं।

16. हमने इस बात का भी सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है कि क्या दूसरे उत्तरवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ की गई टिप्पणियों के अलावा आक्षेपित प्रतिकूल टिप्पणियों पर हमला करने के लिए कोई अन्य आधार बनाया गया था। हमें दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ किए गए व्यक्तिगत हमले के अलावा कोई अन्य आधार नहीं मिला है।

17. अपीलकर्ता रिपोर्टिंग प्राधिकारी को कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल करने में विफल रहा है, जिसने सरकार को अपनी टिप्पणी पेश करते समय अपीलकर्ता के खिलाफ कठोर प्रतिकूल टिप्पणी की थी।

हालाँकि, सुनवाई के समय रिपोर्टिंग प्राधिकारी और समीक्षा प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियाँ भी हमारे सामने रखी गईं। दुर्भाग्य से, रिपोर्टिंग प्राधिकारी को विचाराधीन कार्यवाही में पक्ष-प्रतिवादी नहीं बनाया गया था।

18. हमारे निर्देशानुसार, कर्नाटक सरकार ने अपीलकर्ता के 1978-1979 से 2005-2006 तक के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड हमारे सामने रखे। आक्षेपित प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर, अन्य सभी प्रविष्टियाँ "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छी" और "उत्कृष्ट" हैं। कई अधिकारियों ने अपीलकर्ता को एक स्मार्ट और संतुलित अधिकारी के रूप में दर्ज किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा में आईबी की भूमिका के बारे में उनकी उत्कृष्ट धारणा है और उनके पास मौखिक और लिखित दोनों तरह से संसूचना की उत्कृष्ट शक्ति है और उनका आचरण और चरित्र "बहुत अच्छा" है और उन्होंने एसआईबी के समग्र खुफिया आउटपुट के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ-साथ युवा कर्मचारियों के बीच अपनी छवि भी बढ़ाई है। भी।

19. 25.7.1990 को, स्वीकृति प्राधिकारी, श्री के. सरनयन, अतिरिक्त निदेशक, आईबी मुख्यालय, नई दिल्ली; समीक्षा अधिकारी के आकलन का पूरी तरह से समर्थन किया कि अधिकारी "उत्कृष्ट" है।

20. 1.4.1990 से 31.3.1991 की अवधि के लिए, अपीलकर्ता को एक बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

21. 1.4.1991 से 1.10.1991 की अवधि के लिए, स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ने टिप्पणी की कि "वह डीजीपी की सहायता कर रहा है और निर्देश प्राप्त करने और अच्छा काम करने में गहरी रुचि दिखाता है"।

22. 1.11.1991 से 31.3.1992 की अवधि के लिए, श्री धर्म सिंह ने जो टिप्पणियाँ कीं, उनमें उन्हें काफी जानकार अधिकारी, मेहनती और पूछे जाने पर निष्पक्ष राय दे सकते हैं।

23. 31.3.1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, उन्हें "बहुत अच्छा" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

24. 31.1.1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, उन्हें "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव श्री जे.सी. लिन ने उन्हें "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया।

25. 16.10.1996 से 15.3.1997 तक, आक्षेपित प्रतिकूल टिप्पणियाँ थीं

> "एक अहंकारी अधिकारी, उसके काम का ज्ञान अच्छा है लेकिन वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष नहीं हो सकता।"

26. 1.4.1997 से 18.4.1997 तक उन्हें श्री एस.के. द्वारा "बहुत अच्छा" की श्रेणी में रखा गया है। भट्टाचार्य, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार। हालाँकि, इन सभी वर्षों के लिए, श्री वी.वी. पुलिस महानिदेशक भास्कर ने उन्हें उत्कृष्ट योग्यता वाले अधिकारी की श्रेणी में रखा है।

27. 1.4.1998 से 31.3.1999 तक उन्हें "बहुत अच्छा" श्रेणी में रखा गया है।

28. 1.4.1999 से 31.3.2000 तक, उन्हें "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत उनके कर्मचारी बड़ी संख्या में वन उपज की तस्करी और वन्य जीवन में व्यापार

का पता लगाने में सक्षम थे। और

29. पुलिस महानिदेशक श्री वी.वी. भास्कर ने उन्हें "उत्कृष्ट" श्रेणी में रखा।

30. 14.7.2000 से 28.2.2001 तक श्री सी. दिनाकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त), (द्वितीय उत्तरवादी), पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य, बेंगलुरु ने पैराग्राफ 20 में सामान्य मूल्यांकन इस प्रकार किया:

> "एक अहंकारी और अनुशासनहीन अधिकारी जिसके खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने क्रूर आलोचना की और उसे असंयमित और अनर्गल भाषा का उपयोग करने के लिए 3000/- रुपये (जो उसने भुगतान किया) का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया।"

31. उपरोक्त टिप्पणी को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा उनका आकलन इस प्रकार है-

> "उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। क्रम संख्या 20 पर टिप्पणियाँ 16.10.1996 से 15.3.1997 की अवधि से संबंधित हैं। अधिकारी के बारे में मेरा आकलन यह है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और विभाग के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में गहरी रुचि ली है और उन्हें सौंपे गए अन्य कार्यों जैसे अपराध समीक्षा और फोरेंसिक

विज्ञान प्रयोगशाला की समीक्षा की।"

32. 1.4.2001 से 31.7.2001 तक डॉ. के. श्रीनिवासन, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य, बैंगलोर ने उन्हें सी "उत्कृष्ट" और श्री एम.बी. शासन के गृह एवं परिवहन विभाग भी उक्त ग्रेडिंग से सहमत था।

33. 31.3.2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, उन्हें श्री एम.डी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध और तकनीकी सेवाएँ, बैंगलोर द्वारा "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

34. 1.4.2002 से 30.9.2002 की अवधि के लिए, फिर से श्री एम. डी. सिंह ने उन्हें "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया। श्री वी. वी. भास्कर, महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य ने उन्हें "उत्कृष्ट" का दर्जा दिया और श्री अधिप चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, सरकार ने उन्हें "उत्कृष्ट" के रूप में दर्जा दिया गया। उसी वर्ष, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव, डॉ. ए. रवींद्र ने उन्हें एक उत्कृष्ट अधिकारी के रूप में दर्जा दिया।

35. 31.3.2003 को समाप्त होने वाली अवधि में उनके द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के कारण बैंगलोर में आयोजित 46 वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2002 का आयोजन उत्कृष्ट तरीके से किया गया। उन्होंने वर्ष 2000 और 2001 के लिए "कर्नाटक में अपराध" शीर्षक के साथ अपराध से संबंधित डेटा के प्रकाशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। श्री टी. मुदियाल, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य, बैंगलोर ने

उन्हें "उत्कृष्ट" श्रेणी में रखा।

36. 31.3.2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, श्री टी. मुदियाल ने उन्हें इस प्रकार दर्ज किया:

> "एक बहुत ही जानकार और अनुशासित अधिकारी। उन्होंने सभी विवरणों पर अपना दिमाग लगाया और काम को लगभग पूर्णता के साथ निष्पादित किया। वह एक इच्छुक कर्मचारी हैं और उनके संसूचना कौशल उत्कृष्ट हैं। विभाग में कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वह विभिन्न परिस्थितियों का भली-भांति पूर्वानुमान लगा सकता है और उनके लिए स्वयं को तैयार कर सकता है।
>
> ग्रेडिंग: उत्कृष्ट।"

37. 31.3.2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, श्री के.के. मिश्रा, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, विधान सौधा, बैंगलोर ने इस प्रकार टिप्पणियाँ कीं:

> "सामान्य मूल्यांकन: सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक अधिकारी। तेज और जिज्ञासु दिमाग से संपन्न, उनके पास जबरदस्त वैचारिक क्षमता है जैसा कि उनके नेतृत्व के दौरान कर्नाटक पुलिस कम्प्यूटरीकरण में हासिल की गई लंबी छलांग से साबित हुआ है। उनकी लिखित व मौखिक दोनों संसूचनाओ उनकी पूर्ण स्पष्टता है। उनकी सिद्ध विश्लेषणात्मक और नियोजन क्षमताएं उनके काम में देखी

गई उत्कृष्टता से स्पष्ट हैं। उनके नेतृत्व गुण और पहल हमेशा सामने आए हैं, खासकर जिस तरह से उन्होंने एससीआरबी में सीमित संसाधनों का उपयोग किया है और कई ई-गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की जिनमें पुलिस कंप्यूटरीकरण को महान ऊंचाइयों पर ले जाया गया। विवरणों पर ध्यान देना उनके गुणों में से एक है। अपनी ट्रेडमार्क कड़ी मेहनत और उद्योग के साथ उन्होंने एक अच्छे निर्णय और स्वभाव वाले एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में बेदाग प्रतिष्ठा अर्जित की है, जिसमें एक मजबूत निर्णय और सही और हल्के त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। उनके निपटान की गति उल्लेखनीय है। वह हमेशा मुस्कुराहट के साथ जिम्मेदारी स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। अधीनस्थों, सहकर्मियों और आम जनता के साथ उनके संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण हैं। उन्होंने अधीनस्थों के विकास में असाधारण रुचि दिखाई है और इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, पीएस स्तर पर कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण लागू किया है। उनका जनजातियों और समाज के कमजोर वर्ग के प्रति दृष्टिकोण केवल असंदिग्ध हैं बल्कि करुणा से ओत-प्रोत हैं। नवीन विचारों वाले एक प्रतिभाशाली अधिकारी। वास्तव में आई पी एस के लिए एक संपत्ति है।"

38. कॉलम 5 में की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं;

"उनके पास पुलिस विभाग में कंप्यूटर के उपयोग का बहुत समृद्ध अनुभव है।"

39. कॉलम 6 में, "ऊपर बताए गए कारणों से, अधिकारी उत्कृष्ट ग्रेडिंग का हकदार है।"

40. 31.3.2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, श्री बी.एस. सियाल, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, कर्नाटक राज्य, बैंगलोर ने उनका मूल्यांकन इस प्रकार किया:

"वह अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उन क्षेत्रों में खुद को उत्कृष्ट रूप से पेश कर रहे हैं। वह मेहनती, बुद्धिमान हैं और बहुत अच्छे संसूचना कौशल के साथ दिमाग की स्पष्टता रखते हैं। वह पहल, विवेक और तत्परता से निर्णय लेने वाले अधिकारी है। वह चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता हैं। उसके अधीनस्थों और वरिष्ठों के साथ सौहाद्रपूर्ण संबंध हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के प्रति उनका रवैया सौहार्दपूर्ण, समझदार, दयालु और सहानुभूतिपूर्ण है।

3. सत्यनिष्ठा - संदेह से परे

4. ग्रेडिंग: उत्कृष्ट।"

41. विभिन्न अधिकारियों द्वारा अलग-अलग समय पर की गई

उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता उत्कृष्ट गुणों और योग्यता वाला अधिकारी है। रिपोर्टिंग अधिकारी और दूसरे उत्तरवादी द्वारा समीक्षा प्राधिकारी के रूप में की गई विवादित टिप्पणियों को छोड़कर, उन्हें लगातार "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" और "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। यह सही है कि उन्होंने अपने अभ्यावेदन में असंयमित भाषा का इस्तेमाल किया है, मुख्य रूप से उत्तरवादी नंबर 2 के खिलाफ, इस गलत धारणा पर कि प्रतिकूल टिप्पणी उक्त उत्तरवादी द्वारा की गई थी, लेकिन इस तरह की असंयमित भाषा के उपयोग को वस्तुनिष्ठ रूप से हमारे सामने सभी वर्षों की सभी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार कर देखा जाना चाहिए। इस बात पर विचार करना होगा कि क्या रिपोर्टिंग अधिकारी और समीक्षा अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियाँ "औसत" के समग्र मूल्यांकन के लिए अपने आप में पर्याप्त थीं। जबकि इसकी अपेक्षा प्रश्नगत अवधि के पहले और बाद में गोपनीय रिपोर्टों में लगातार उत्कृष्ट टिप्पणियां थीं। दरअसल, अपीलकर्ता के 14.7.2000 से 28.2.2001 तक के प्रदर्शन के लिए द्वितीय उत्तरवादी द्वारा किए गए सामान्य मूल्यांकन से असहमत होते हुए, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, गृह और परिवहन विभाग की टिप्पणियाँ भी विचारणीय हैं।

42. गोपनीय रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह एक अधिकारी के प्रदर्शन और उसके करियर में आगे की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए बुनियादी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

इस न्यायालय ने माना है कि सी.आर.एस. के माध्यम से प्रदर्शन मूल्यांकन का उपयोग मानव संसाधन विकास के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए और इसका उपयोग दोष खोजने की प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में किया जाना चाहिए। लगभग 150 दिनों की छोटी अवधि के लिए विवादित प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर, अपीलकर्ता का प्रदर्शन विभिन्न उपलब्धियों वाला और प्रतिष्ठित पोस्टिंग और भारत के राष्ट्रपति से मेधावी पुरस्कारों के साथ लगातार उच्च गुणवत्ता वाला रहा है। हम पहले ही देख चुके हैं कि अपीलकर्ता को अपने पूरे करियर के

दौरान "बहुत अच्छा", "उत्कृष्ट" और "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह समझना मुश्किल है कि जिस 150 दिन की अवधि के लिए प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गई थीं, उस अवधि में यह कैसे प्रतिकूल हो सकता है। इसके अलावा, ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद, कर्नाटक सरकार ने उनकी योग्यता और क्षमता और उत्कृष्ट गुणों को देखते हुए, अपीलकर्ता को पहले ही पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत कर दिया है।

43. हालाँकि, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार सवाल उठाया गया है जैसे कि वे उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा की गई थीं, न्यायालय को यह भी यह आकलन करना होगा कि क्या अपीलकर्ता के लगातार अच्छे प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए टिप्पणियां उचित थीं। यहां तक कि अपने अभ्यावेदन में उत्तरवादी नंबर 2

के खिलाफ उनका आक्रोश भी ऐसी धारणा का परिणाम प्रतीत होता है, जिसकी अपीलकर्ता के रैंक और क्षमता के अधिकारी से निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन, हमारे विचार में, इसे अन्यथा बेदाग और उत्कृष्ट करियर के रास्ते में नहीं आना चाहिए।

44. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता के अभ्यावेदन में असंयमित आक्रोश से पूर्वाग्रहग्रस्त था, जिसके कारण रिट याचिका खारिज कर दी गई। इस तरह के पूर्वाग्रह के कारण, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के लगातार अच्छे रिकॉर्ड को नजरअंदाज करने का फैसला किया और अपीलकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व में इस्तेमाल की गई भाषा के आधार पर अपना निर्णय दिया। इसके अलावा, उच्च न्यायालय इस बात की विवेचना करने में भी विफल रहा कि "मुस्कुराने के अलावा कुछ भी", "अपने वरिष्ठों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता" और "उनकी निर्णय लेने की क्षमता उनके प्रतिमान द्वारा शासित थी" जैसी टिप्पणियां प्रतिकूल नहीं हैं या इन्हें अपीलकर्ता की ए.सी.आर. में औसत रेटिंग को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था।

45. खुद को संतुष्ट करने के लिए हमने अपीलकर्ता का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड मांगा था और उसका अवलोकन करने पर, हमने पाया कि संबंधित अवधि के लिए रिपोर्टिंग अधिकारी की टिप्पणियाँ उसके लगातार प्रदर्शन के विपरीत थीं। उत्तरवादी संख्या 2 की यह टिप्पणी कि अपीलकर्ता एक अहंकारी अधिकारी था, उसके बाद उसकी टिप्पणी है कि उसका ज्ञान और कार्य अच्छा है। हमारे निर्णय में ऐसा अवलोकन, औसत की समग्र

रेटिंग का आधार नहीं हो सकता।

46. ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल अपीलकर्ता द्वारा दूसरे उत्तरवादी के खिलाफ इस्तेमाल की गई असंयमित भाषा से पूर्वाग्रहग्रस्त था। ट्रिब्यूनल ने यह मानते हुए कि ऐसी भाषा पूरी तरह से अस्वीकार्य है, अपीलकर्ता पर दूसरे उत्तरवादी को भुगतान करने के लिए 3,000/- रुपये का खर्चा भी लगाया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त लागत का भुगतान अपीलकर्ता द्वारा दूसरे उत्तरवादी को कर दिया गया है। हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से ही,

हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता के अन्यथा लगातार अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करने में भी त्रुटि की है।

47. उपरोक्त कारणों से, हम सिविल अपील स्वीकार करते हैं और रिट याचिका संख्या 3310/ 2005 में ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रश्नाधीन अवधि के दौरान अपीलकर्ता के प्रदर्शन को औसत के रूप में विचार न करें। अपीलकर्ता को अपने आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करते समय भविष्य में असंयमित और अपमान जनक भाषा का उपयोग करने से भी बचना चाहिए।

48. खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार।

नोट - यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजंस टूल 'सुवास' की सहायतस से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आलोक सुरोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

(आलोक सुरोलिया)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द